Proposal for development of Eastern Ghats

2097. DR. NARREDDY THULASI REDDY;

SHRI V. HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government of An. dhra Pradesh have submitted a proposal for the development of the Eastern Ghats; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOM-ANGO); (a) and (b) In December, 1989; the Government of Andhra Pradesh had sought to include the Eastern Ghats under Hill Area Development Programme (HADP). The Proposal was to cover 26 mandals from five districts viz. Srikakulam, Vizianagram, Visakhapatnam, East-Godavari and West Godavari under HADP.

The proposal has been considered and it has been decided not to in. elude any new hill areas under HADP.

Constitution of a Small Farmers Agri-business consortium

2098. SHRI MENTAY PADMANA-BHAM:

SHRI KAMAL MORARKA:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENT. ATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have solved the proposal to constitute a small farmers Agri-business consortium;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that Government dropped the proposal because of the serious differences between the Planning Commission and the Agriculture Ministry;

(d) whether any steps are proposed to be initiated to resolve the differences; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOM. ANGO): (a) No, Sir.

(b) to (e) Questions do not arise.

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति

2099. श्री शान्ति त्यागी :

श्री रामजीलाल :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के अंत तक और 28 फरवरी, 1993 को स्थिति के अनुसार, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी थी ;

(ख) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में उन परिवारों की संख्या में वृद्धि/कमी हुई है ; और

(घ) सरकार द्वारा उन परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग जिन वर्षों के लिए संपूर्ण प्रतिदर्श आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण संगठन से परिवार उपभोक्ता व्यय के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, उन वर्षों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों/रिवारों की राज्यवार संख्या का अनुमान

लगाता है। गरीबी के अद्यतन राज्यवार अनुमान वर्ष 1987–88 के लिए उपलब्ध है। गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है। (नीचे देखिए) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यवार अनुमान वर्ष 1983–84 के लिए उपलब्ध है। गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) गरीबी के वर्षवार अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) गरीब परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपाय के रूप में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इनमें आय बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा नेहरू रोजगार योजना (एन० आर० वाई०) जैसे कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लाभों को विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एससीपी) तथा आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) कार्यान्वित की जा रही है जिनका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों को लाभ पहुंचाना है।

विवरण–I

गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशतता–1987–88
(अनंतिम)

क्र० सं०	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	आंध्र प्रदेश	195.70	31.7
2	असम	52.89	22.3
3	बिहार	336.54	40.8
4	गुजरात	73.25	18.4
5	हरियाणा	18.15	11.6
6	हिमाचल प्रदेश	4.52	9.2
7	जम्मू और कश्मीर	9.79	13.9
8	कर्नाटक	136.46	32.1
9	केरल	48.98	17.0
10	मध्य प्रदेश	224.97	36.7
11	महाराष्ट्र	214.10	29.2
12	उड़ीसा	135.12	44.7
13	पंजाब	13.88	7.2
14	राजस्थान	99.54	20.4
15	तमिलनाडु	176.85	32.8
16	उत्तर प्रदेश	448.34	35.1
17	प० बंगाल	173.45	27.6
18	छोटे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	14.2	7.7
19	अखिल भारत	2376.7	29.9

विवरण–II

गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रतिशतता—1983–84

राज्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		समस्त जनसंख्या	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	51.0	43.3	48.4	43.3	38.67	29.52
असम	21.9	42.8	25.5	20.2	23.76	21.56
बिहार	71.1	52.2	64.9	39.8	51.35	37.04
गुजरात	39.9	19.3	52.1	56.6	27.62	17.34
हरियाणा	27.9	40.1	0	39.3	15.19	16.92
हिमाचल प्रदेश	23.5	11.7	7.5	11.5	14.01	7.99
जम्मू और कश्मीर	32.9	27.5	0	0	16.40	15.81
कर्नाटक	54.1	36.6	59.9	45.2	37.49	29.19
केरल	43.9	42.2	36.1	51.7	26.05	30.09
मध्य प्रदेश	59.3	45.8	67.1	34.0	50.30	31.09
महाराष्ट्र	55.9	44.8	58.7	41.3	41.50	23.33
उड़ीसा	54.9	40.3	68.9	52.8	44.76	29.29
पंजाब	21.8	33.0	15.4	47.1	10.87	21.00
राजस्थान	44.9	33.7	63.7	48.1	36.63	26.12
तमिलनाडु	59.4	54.5	50.9	51.1	44.08	30.89
उत्तर प्रदेश	57.3	46.3	45.8	24.3	46.48	40.25
पश्चिमी बंगाल	52.0	41.3	58.6	33.1	43.84	26.52
अखिल भारत	53.1	40.4	58.4	39.9	40.40	28.10

उत्तर प्रदेश में नये पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खंडों (ब्लाकों) को धन का आवंटन

2100. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में किन-किन विकास खंडों (ब्लाकों) का पता लगाया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले संभावित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश में कितना धन आवंटित किया गया है ?

योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : योजना आयोग को ऐसे किसी पैकेज कार्यक्रम की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।